

1. अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आर एस एस प्रमुख मोहन भागवत और गृह मंत्री अमित भाह ने स्वातंत्र्यवीर सावरकर की भव्य प्रतिमा का बिडनाबाद में अनावरण किया।
2. कैबिनेट ने दो हजार सत्ताईस डिजिटल जनगणना को मंजूरी दी। जनगणना के लिए ग्यारह हजार सात सौ अटठारह करोड़ का बजट भी स्वीकृत किया।
3. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज बढ़ाने के लिए कर्मचारी नामांकन योजना की शुरु करने की घोषणा की।
4. उद्योग विभाग द्वारा ननकौड़ी द्वीप समूह में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।



अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आज एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत की उपस्थिति में स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर की भव्य प्रतिमा का राजधानी श्री विजयपुरम के निकट स्थित बिडनाबाद में अनावरण किया गया। इसी अवसर पर 'वीर सावरकर प्रेरणा पार्क' का भी आधिकारिक उद्घाटन किया गया। महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों को काला पानी के सजा के तहत अंडमान स्थित सेल्युलर जेल में कठोर यातनाएं दी गई थी। वीर सावरकर ने जेल की कठिन परिस्थितियों के बीच भी राष्ट्रभक्ति, अनुशासन और मानसिक दृढ़ता का परिचय दिया। उनके लेखन और क्रांतिकारी विचारों ने स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा मिली। नव-निर्मित 'वीर सावरकर प्रेरणा पार्क' को इस ऐतिहासिक विरासत और सावरकर के राष्ट्रीय योगदान के सम्मान में विकसित किया गया है। पार्क में स्थापित प्रतिमा को सावरकर की अदम्य राष्ट्र, निष्ठा और सांस्कृतिक जागरण के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। आयोजकों के अनुसार, इस पार्क का उद्देश्य आने वाली पीढ़ियों को स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास से जोड़ना और उन्हें राष्ट्रहित के प्रति समर्पण की प्रेरणा देना है। इस कार्यक्रम में द्वीप समूह के उप राज्यपाल एडमिरल डी.के. जोशी भी उपस्थित रहे।



केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दो हजार सत्ताईस की जनगणना के लिए ग्यारह हजार सात सौ अटठारह करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह जनगणना दो चरणों में होगी और यह दुनिया की सबसे बड़ी सांख्यिकीय और प्रशासनिक प्रक्रिया मानी जाती है। दो हजार सत्ताईस की जनगणना डिजिटल होगी, जिसमें मोबाइल ऐप्स के जरिए डेटा संग्रह किया जाएगा। इसके तहत तीस लाख कार्यकर्ता जनगणना में शामिल होंगे और जाति गणना भी की जाएगी।



संघ लोक सेवा आयोग ने विशिष्ट दिव्यांगजनों-पीडब्ल्यूबीडी के लिए परीक्षाओं को अधिक सुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम की घोषणा की है। आयोग अब यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे प्रत्येक दिव्यांगजन उम्मीदवार को आवेदन पत्र में उल्लिखित उनकी पसंद का केंद्र मिल सके। इस प्रक्रिया के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग सबसे पहले विशिष्ट दिव्यांगजनों-पीडब्ल्यूबीडी और गैर-विशिष्ट दिव्यांग उम्मीदवारों दोनों के लिए प्रत्येक केंद्र की मौजूदा क्षमता का उपयोग करेगा। आयोग के अध्यक्ष डॉ.अजय कुमार ने कहा है कि यह फैसला पिछले पांच वर्ष में परीक्षा केंद्रों के आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर लिया गया है।



राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पूर्व केंद्रीय मंत्री शिवराज पाटिल के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अपने लम्बे सार्वजनिक जीवन के दौरान श्री पाटिल लोकसभा अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल और सांसद जैसे अनेक महत्वपूर्ण पदों पर रहे। विभिन्न भूमिकाओं में उनकी सेवाएं हमेशा याद रखी जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि श्री पाटिल एक अनुभवी राजनेता थे। वे हमेशा समाज के हित में योगदान के लिए तत्पर रहते थे।



श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा कवरेज बढ़ाने के लिए कर्मचारी नामांकन योजना, शुरू करने की घोषणा की है। यह योजना नवंबर से तीस अप्रैल दो हजार छब्बीस तक लागू रहेगी। योजना के तहत नियोक्ता उन कर्मचारियों का नामांकन कर सकेंगे, जो एक जुलाई दो हजार सत्रह से इक्तीस अक्टूबर दो हजार पच्चीस के बीच कार्य पर शामिल हुए हों लेकिन अब तक EPF में

पंजीकृत न किए गए हों। इस योजना में पिछली अवधि के लिए कर्मचारी अंशदान पूरी तरह माफ होगा, जबकि नियोक्ता को केवल अपना अंशदान जमा करना होगा। योजना में पंजीकृत प्रतिष्ठान, निर्धारित शर्तों के अनुसार, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के लाभ भी ले सकेंगे। सरकार का मानना है कि यह पहल सामाजिक सुरक्षा के दायरे का विस्तार करेगी और नियोक्ताओं के लिए अनुपालन प्रक्रिया को सरल बनाएगी। विस्तृत जानकारी मंत्रालय और EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।



निर्वाचन आयोग ने आठ प्रमुख राज्यों—जिनमें पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और केरल शामिल हैं—में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की निगरानी के लिए विशेष मतदाता सूची पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। आयोग के अनुसार, पर्यवेक्षक अपना काम शुरू कर चुके हैं और फरवरी 2026 में अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होने तक सप्ताह में दो दिन संबंधित राज्यों में उपलब्ध रहेंगे। SROs राष्ट्रीय और राज्य स्तर की सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के साथ बैठकें करेंगे। वे संबंधित राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों और जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ भी प्रत्यक्ष या वर्चुअल बैठकें करेंगे ताकि संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी और सुचारु रूप से पूरी हो सके। इन पर्यवेक्षकों का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र मतदाता छूटे नहीं और कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न हो।



उद्योग विभाग की ओर से ननकौड़ी द्वीप समूह के विभिन्न क्षेत्रों में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और अन्य सरकारी प्रायोजित योजनाओं पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य इच्छुक उद्यमियों को प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और विभाग की अन्य योजनाओं के बारे में जानकारी देना था। यह कार्यक्रम जनजातीय परिषदों, बैंकों और संबंधित विभागों के सहयोग से कच्छल, ननकाड़ी और कमोर्टा द्वीप में आयोजित किया गया। इस अवसर पर क्षेत्र के लगभग डेढ़ सौ युवाओं ने भाग लिया। युवाओं को PMEGP योजना के तहत विनिर्माण, सेवा और व्यवसाय क्षेत्र में स्वरोजगार स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इस दौरान PMEGP योजना के तहत स्वरोजगार के अवसर का लाभ उठाने के इच्छुक युवाओं को ऑनलाइन दस्तावेजीकरण प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी दी गई।



शिक्षा निदेशालय, की विज्ञान शाखा द्वारा प्रयोगशाला सहायकों और परिचारकों के लिए पांच दिवसीय “व्यवहारिक विज्ञान प्रयोगशाला प्रयोग आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम” का आज समापन हुआ। यह कार्यक्रम राजकीय मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, राजकीय बालक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, और राजकीय आर.बी.वी. वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कक्षा नवीं से बारहवीं तक के प्रतिभागियों के लिए प्रयोगशाला प्रयोगों को संचालित करने की क्षमता और प्रयोगशाला उपकरणों की सुरक्षित संचालन पर ध्यान केन्द्रित करना था। कार्यक्रम में द्वीप समूह के विभिन्न स्कूलों के कुल सतानब्बे प्रयोगशाला सहायकों और परिचारकों ने भाग लिया।



अंडमान निकोबार प्रशासन के कृषि विभाग ने उच्च मूल्य कृषि विकास एजेंसी के सहयोग से, एकीकृत बागवानी विकाश मिशन के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद—राष्ट्रीय कृषि कीट संसाधन ब्यूरो, बेंगलुरु में “बायो-एजेंट्स के व्यापक उत्पादन” पर तीन दिवसीय व्यावहारिक प्रशिक्षण का आयोजन किया। बायो-एजेंट्स का उपयोग रासायनिक कीटनाशकों पर निर्भरता कम करने, पर्यावरण को सुरक्षित रखने और द्वीप समूह के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए उपयुक्त हैं। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ कीट प्रबंधन में क्षेत्रीय स्तर के अधिकारियों की तकनीकी क्षमता को मजबूत करना था। इस अवसर पर द्वीप समूह की प्रमुख फसल, नारियल के पेड़ों से संबंधित कीट प्रजातियों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया।

